संपादकीय

# पंजाब में कैप्टन की विदाई

**कांग्रेस** आलाकमान के निर्देश पर हो रही विधायक दल की बैठक से पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे कर कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने दो साफ संकेत दे दिए हैं : एक, सोनिया गांधी किसी को भी नया मुख्यमंत्री बनाएं, उसकी राह आसान नहीं होगी। दो, कैप्टन और कांग्रेस का साथ अब ज्यादा नहीं बचा है। सीधे राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कैप्टन की टिप्पणियों से साफ है कि कांग्रेस आलाकमान और उनके बीच अविश्वास गहरा हो चुका है। यह बहस का विषय है कि इसके लिए वह खुद ज्यादा जिम्मेदार हैं या फिर इसका श्रेय उनके विरोधियों के एक सूत्रीय अभियान को दिया जाए। यह सही है कि 2017 में भी कैप्टन कांग्रेस की पसंद कम, मजबूरी ज्यादा थे। इसके बावजूद वह प्रताप सिंह बाजवा सरीखे पुराने कांग्रेसियों के विरोध को सफलतापूर्वक झेल गये थे, लेकिन क्रिकेटर से राजनेता बने और भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू अंततः उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई कराने में सफल हो गए। बेशक, यह कांग्रेस की राजनीति पर भी एक सवालिया निशान है कि दूसरे दल से आया नेता पार्टी के दो बार के मुख्यमंत्री पर भारी पड़ा। वह भी तब, जब नौ माह से केंद्र के कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन के चलते कैप्टन की लोकप्रियता बेहतर मानी जा रही थी। हालांकि कैप्टन इससे इंकार करते हैं, पर सिद्धू का आरोप है कि चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए, पर छह माह में नया मुख्यमंत्री क्या चमत्कार कर देगा संतुलन बिठाने की खातिर कैप्टन की मर्जी के खिलाफ सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद विधानसभा चुनाव से बमुश्किल छह महीने पहले अब मुख्यमंत्री भी बदलने का आत्मविश्वास क्या कांग्रेस आलाकमान को भाजपा द्वारा गुजरात में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार ही बदल देने से आया है! अगर ऐसा है तो यह अति विश्वास आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि पंजाब की राजनीति भी अब दो ध्रुवीय नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी इस बार भी सत्ता की दावेदार होगी। अकाली दल भी बसपा से गठबंधन कर चुनावी बिसात बिछा चुका है। अकाली दल की पुरानी जोड़ीदार भाजपा अवश्य इस बार अलग-थलग नजर आ रही थी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ होने के लाभ के अलावा कैप्टन की नाराजगी भी अब उसके लिए नयी संभावनाओं को जन्म दे सकती है।

# पुरानी दोस्ती, नई कहानी

नजरिया | फीचर

**वैश्विक** जगत में भारत का अस्तित्व संबंधों से अधिक नीतियों पर आधारित है, वह नीतियां जो वेदों की चर्चाओं से करीब 7 दशक के अध्ययन से प्राप्त हुई हैं, लेकिन यह भी सच है कि, नीतियों को विस्तार विश्व पटल पर भूमिका बांधने से ही मिला है, और अब जबकि विश्व की भू-राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन देखा जा रहा है, तब इस भूमिका को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता महसूस होने लगी है।

सवाल यह है कि, भूमिका को विस्तार देकर बदलते समीकरणों को स्थायित्व देगा कौन? भारत के संबंधी क्वाड के देश या सुपर पावर का बाना धारण करने वाला अमेरिका? विश्व भर में जोर पकड़ती इन चर्चाओं के बीच अफगानिस्तान को लेकर भारत अब फ्रंटफुट पर खेल रहा है। इस सप्ताह शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन कर रहे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को इशारों-इशारों में कड़ी फटकार लगाई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी था, इसलिए चीन-पाकिस्तान इस फटकार का बुरा न मानकर इसे उस अवसर का रिटर्न गिफ्ट भी मान सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 24 सितम्बर से शुरू हो रहे अमेरिका के तीन दिनों के दौरे में अभी इन दोनों देशों के हिस्से में और भी फटकार आने वाली है, लेकिन पहले बात शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक की। प्रधानमंत्री ने इसमें एकदम खुले शब्दों में कहा कि कट्टरपंथ जिस तेजी से दुनिया में बढ़ रहा है और हाल में अफगानिस्तान में जिस तरह संवाद के बजाय हिंसा के दम पर सत्ता हस्तांतरित हुई, उससे दुनिया में शांति, सुरक्षा और आपसी भरोसे को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को समर्थन दे रहे देशों को उन्होंने अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपंग दोनों बैठक में मौजूद थे। काबुल में चीन का दूतावास पहले की तरह ही काम कर रहा है और जिनिपंग बीजिंग में तालिबान के नेताओं से मिल भी चुके हैं। वहीं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल अब कोई राज की बात नहीं रह गई है।

अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वो ताजिकिस्तान, ईरान समेत कई देशों की चिंताएं बढ़ा रहा है। खबर है कि अल-कायदा वहां नये सिरे से सक्रिय हो चुका है। इससे आतंकवाद को लेकर रूस की चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उसकी तालिबान नीति में यू-टर्न आ गया है, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के अचानक वापस लौट जाने का सबसे ज्यादा खमियाजा तो भारत को ही उठाना पड़ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के एजेंडे में यह बात प्रमुखता से शामिल भी की गई है। अमेरिका ही क्यों, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर देश भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करने में हिचकेंगे और यह पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़े सबक जैसा होगा। 24 सितम्बर को क्वाड के शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 50 मिनट की वन-टू-वन बैठक होगी। दोनों के बीच यह पहली आमने-सामने की भेंट होगी। इसके पहले की पिछली तीन मुलाकातें वर्चुअल थीं। क्वाड की बैठक में जहां कोविड वैक्सीन निर्माण, महत्त्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर बात होगी, वहीं द्विपक्षीय वार्ता का फोकस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन पर रहेगा। कोरोना के प्रसार के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कोई विदेशी दौरा कर रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के प्रोटोकॉल को खुद पर भी लागू करते हुए उन्होंने इस अवधि में विदेशी दौरों से परहेज बरता है। भारत के नजरिए से प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद जरूरी भी हो गया था, क्योंकि अमेरिका की नीतियों से भारत सीधे-सीधे प्रभावित होता दिख रहा है। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाकर अमेरिका अब अपनी पूरी शक्ति चीन पर लगाना चाहता है। दोनों ही मामलों में भारत के हित जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से आतंकियों को मिली खुली छूट का खतरा है, तो दूसरी तरफ चीन से विस्तारवाद की चुनौती।

जाहिर तौर पर इस बातचीत का एक एजेंडा पाकिस्तान भी रहेगा। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान से अपने रिश्तों के नये सिरे से मूल्यांकन की बात कही है। इस बयान में गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए अमेरिका ने इस बात को आधार बनाया है कि अफगान-तालिबान मसले पर पाकिस्तान की दिलचस्पी वाले कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो अमेरिका के लिए असुविधाजनक हैं। प्रधानमंत्री मोदी यकीनन जो बाइडेन से यह जानने के लिए उत्सुक रहेंगे कि अमेरिका क्या वाकई पाकिस्तान से अपने रिश्तों को लेकर कोई नई रणनीति बनाने जा रहा है या फिर ब्लिंकन का ये बयान भी पाकिस्तान को समय-समय पर घुड़की देते रहने वाली पुरानी अमेरिकी परंपरा की रस्म अदायगी भर है। अमेरिकी दौरे पर भारत के लिए एक और महत्त्वपूर्व विषय रहेगा 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सेंक्शंस एक्ट' (कास्टा) से जुड़ी अनिश्चितता को दूर करना।

रूस से कोई बड़ी रक्षा खरीद करने वाले देश पर अमेरिका इसी कानून के तहत प्रतिबंध लगाता है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने तुर्की पर इसी कानून के तहत कार्रवाई की थी, जबकि वो नाटो में उसका सहयोगी है। भारत ने ट्रंप प्रशासन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अक्टूबर 2018 में रूस से एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच इकाइयों के लिए पांच अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया था और पिछले साल ही पहली किस्त के तौर पर 800 मिलियन डॉलर रूस को दे भी दिए गए। हालांकि अमेरिका कह चुका है कि कास्टा का उद्देश्य दोस्त देशों पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन भारत कानून की तलवार को लटकाए रखने के बजाय स्पष्टता चाहेगा कि इस बयान में जिन दोस्त देशों का संदर्भ दिया गया है, उसमें वह शामिल है या नहीं। वैसे भी भारत की यह खरीद अपनी सरहदों की चौकसी बढ़ाकर चीन को रोकने के मकसद से की गई है। क्वाड से लेकर ऑकुस तक का यही उद्देश्य भी है और अमेरिका इन दोनों ही समूहों में शामिल है। क्वाड तो खैर अपने गठन से ही चीन की आंख की किरकिरी बना हुआ है, लेकिन ऑकुस अपेक्षाकृत नया समूह है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ये साझा मंच तैयार किया है। इसके जरिए अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने में सहयोग करेंगे और उन्हें अपने समुद्री क्षेत्र में तैनात करने में मदद करेंगे, जिससे कि चीन पर नकेल कसी जा सके।

अमेरिका ने 50 साल बाद किसी देश से परमाणु पनडुब्बी की तकनीक साझा की है। इससे पहले उसने केवल ब्रिटेन को यह तकनीक बताई थी। पनडुब्बी तकनीक भले ही ऑस्ट्रेलिया को मिल रही हो, लेकिन भारत के लिहाज से यह इसलिए राहत की बात होनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए जो बाइडेन अफगानिस्तान से ध्यान हटाकर उसे चीन पर केंद्रित करने के अपने वादे को पूरा करते दिख रहे हैं। इस संदर्भ में ऑकुस से बाहर रहकर भी यह भारत के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यूएनजीए को संबोधित करना भी होगा। दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि इसमें प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन के साथ आतंकवाद को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं। यह और बात है कि प्रधानमंत्री जिस मंच पर अपनी राय दुनिया से साझा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का वही मंच वैश्विक रुचि के अधिकतर मसलों की ही तरह अफगानिस्तान और आतंकवाद के मामले में भी अपनी साख के मुताबिक कोई सार्थक पहल नहीं कर पाया है।

# एक भारत, श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आपसी एकता, तालमेल और मैत्री की स्थापना

**विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कई स्तरों पर आपसी मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए तथा विविधता का उत्सव मानते हुए यह कार्यक्रम भारत की एकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के जरिये, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आपसी समझ और अपनी विविध संस्कृतियों के पहलुओं को साझा करके, राष्ट्रीय पहचान की संयुक्त भावना का अनुभव करते हैं। वे एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में नियमित मैत्री के जरिये राष्ट्रीय पहचान का अनुभव करते हैं।**

हम भारतीयों ने हमेशा अपनी मातृभूमि को एक सभ्यता संपन्न राष्ट्र के रूप में देखा है। ऐसे राष्ट्र की सभ्यता की सीमाएं, राष्ट्र की संस्कृति की पहुंच, उसके लोकाचार तथा एक-दूसरे को व्यापक रूप से जोड़ने वाली आध्यात्मिक भावना के प्रभाव से तय होती हैं। परिणाम स्वरूप, राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा, भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है- वसुधैव कुटुम्बकम। दूसरी ओर, यूरोप और पश्चिम के देशों ने क्षेत्रीय सीमाओं, मानचित्रों और इन क्षेत्रों के भीतर कानून को लागू करने की क्षमता पर आधारित राष्ट्रीय सीमाओं को प्राथमिकता दी। भारत की क्षेत्रीय एवं सभ्यातगत सीमाओं के अधिकतम संभव सीमा तक निकटता से जुड़े रहना सुनिश्चित करने में अगर किसी व्यक्ति का असाधारण योगदान था, तो वे थे-सरदार वल्लभभाई पटेल।

इस पृष्ठभूमि में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का शुभारंभ करना सर्वाधिक उपयुक्त था। सरदार पटेल की जयंती से पहले, 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरदार पटेल ने हमें एक भारत दिया और अब यह 125 करोड़ भारतीयों का परम कर्तव्य है कि वे सामूहिक रूप से इसे श्रेष्ठ भारत बनाएं।' इसके बाद, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा, 'सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता की भावना को प्रमुखता देनी होगी। एक-दूसरे की समझ को मजबूत करने के लिए', संरचनात्मक तरीके से विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच घनिष्ठ आपसी सम्बन्ध बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यों और जिलों को आपस में जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम के तहत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' को शुरू किया जाएगा, जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ेगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले राज्यों और जिलों के बीच आपसी सहमति के जरिए हम इसे सफल बनायेंगे।'

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कई स्तरों पर आपसी मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए तथा विविधता का उत्सव मानते हुए यह कार्यक्रम भारत की एकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के जरिये, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आपसी समझ और अपनी विविध संस्कृतियों के पहलुओं को साझा करके, राष्ट्रीय पहचान की संयुक्त भावना का अनुभव करते हैं। वे एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में नियमित मैत्री के जरिये राष्ट्रीय पहचान का अनुभव करते हैं। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एक ऐसी भावना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचती हैं, एक-दूसरे से जुड़ती हैं और परस्पर संवाद करतीं हैं। इसके माध्यम से एक ओर अलग-अलग विशेषताओं से युक्त तथा दूसरी ओर एक महानगरीय समाज को आपसी सम्बन्ध और भाईचारे की सहज भावना को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। यह घनिष्ठ सांस्कृतिक जुड़ाव और बातचीत, लोगों में समग्र राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना प्रेरित करती है। यह राष्ट्र निर्माण की भावना और सभी को लाभ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भागीदार राज्यों के विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान-प्राप्ति का इकोसिस्टम बनाना है, ताकि दो राज्यों के बीच संपर्क की स्थापना से वे दूसरे राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर उनसे लाभ प्राप्त कर सकें।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम की बेहतर समझ देशवासियों में अन्य संस्कृतियों को देखने व जानने के लिए उत्सुकता पैदा करती है। इस प्रकार वे पर्यटन और पर्यटन से लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह बात, हम सभी को याद है कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कम से कम 15 पर्यटन स्थलों का दौरा करने के लिए सभी देशवासियों को प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री ने महसूस किया था कि इसके माध्यम से पूरे देश में पर्यटन का स्वतः विकास होगा और इसके साथ ही नागरिकों को देश के सुन्दर गंतव्यों और भारत की प्राकृतिक सुंदरता तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के विजन और नेतृत्व ने पर्यटन मंत्रालय की पहल 'देखो अपना देश' और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' जैसे कार्यक्रमों के बीच गहरे तालमेल और आपसी निकटता को संभव बनाया है।

अधिक से अधिक वैक्सीन की डोज दिए जाने से, पर्यटन क्षेत्र जनवरी 2022 से पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम होगा और 'अतुल्य भारत' की अंतर्निहित ताकत 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की मूल भावना का लाभ उठाकर समृद्धि प्राप्त करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत, राज्यों का एक संघ है। इसका अर्थ है कि संघ का विनाश नहीं हो सकता, अर्थात यह अविनाशी है। यह अनूठा संघ धर्मों, संस्कृतियों, जनजातियों, भाषाओं, व्यंजनों और लोगों का एक विविध संयोजन है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, जो इतना विविध, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक हो, फिर भी साझी परंपराओं, संस्कृतियों और मूल्यों के प्राचीन बंधनों से परस्पर जुड़ा हो। हमारे देश की विविधता की रक्षा और संरक्षण करने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए अनगिनत बलिदानों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के साथ न्याय करना है, जिन्होंने 565 देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने का महान कार्य किया था।

**(जी. किशन रेड्डी केन्द्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।)**

आजकल

# प्रधानमंत्री की कट्टरपंथ पर चोट

**शंघाई** सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात के प्रसंगवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेताया कि कट्टरपंथ क्षेत्रीय शांति के लिये बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है, जिसके लिये एससीओ देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित सम्मेलन में पाक प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मोदी ने चेताया कि कट्टरपंथ के चलते युवाओं को तकनीकी विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है और क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का दोहन नहीं हो पा रहा है। दरअसल, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान की अध्यक्षता में हाइब्रिड प्रारूप के शिखर सम्मेलन में रूस, चीन व पाक समेत आठ देश भाग ले रहे हैं। हाइब्रिड इस मायने में कि आयोजन का कुछ हिस्सा डिजिटल आधार पर तथा शेष हिस्सा आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सम्मेलन को सम्बोधित किया, वहीं विदेश मंत्री जयशंकर सम्मेलन में भाग लेने दुशांबे में मौजूद हैं जहां उन्होंने सीमा अतिक्रमण के मुद्दे पर चीनी समकक्ष से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सामान्य रिश्तों का रास्ता सीमा पर शांति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की चुनौती को मिलकर निपटने की बात करते हुए कहा कि मध्य एशिया में इस्लाम से जुड़ी शांति, सहिष्णु और समावेशी संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस सम्मेलन के जरिये दुनिया को इस्लामिक कट्टरपंथ की चुनौतियों के प्रति आगाह किया। मोदी ने माना कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों की सत्ता आने से क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। प्रतीकों के जरिये प्रधानमंत्री ने पाक को चेताया कि देर-सवेर कट्टरपंथ उसके लिये खतरा बन सकता है। लोकतांत्रिक सरकार के दौरान जो आतंकी संगठन नियंत्रण में थे, अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद वे स्वच्छंद व्यवहार करने लगे हैं। उन्होंने चेताया कि यह पूरा क्षेत्र कट्टरपंथी ताकतों के लिये सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। दरअसल, सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों की वापसी के बाद अन्य इस्लामिक देशों में भी सख्त शरिया कानून लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान में भी वहाबी इस्लाम का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि मोदी ने कहा कि मध्य एशिया के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह उदार व प्रगतिशील मूल्यों का गढ़ रहा है। यहां सूफीवाद की उदारवादी परंपराएं सदियों तक पनपी व पूरे विश्व में इनका विस्तार हुआ, जिसकी झलक आज भी इन देशों की सांस्कृतिक विरासत में देखने को मिलती है। भारत समेत एससीओ के इन देशों में इस्लाम से जुड़ी उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं व परंपराएं मौजूद हैं। इन हालात में एससीओ को कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। उन्होंने कट्टरपंथ से मुकाबले के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा व परस्पर विश्वास की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिसे उन्होंने नयी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिये अनिवार्य शर्त भी माना।

# ब्रह्मांड की उलझी गुत्थियां

दृष्टिकोण | निरंकार सिंह

**हमारा** ब्रह्मांड कैसे और कब बना, इस रहस्य की गुत्थी आज भी अनसुलझी ही है। आजकल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसी अदृश्य ऊर्जा (डार्क एनर्जी) और अदृश्य पदार्थ (डार्क मैटर) पर बहस चल रही है। हालांकि अदृश्य ऊर्जा की परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले ही कर ली थी। उनके सिद्धांतों में 'डार्क एनर्जी' की भी जगह थी। हालांकि वे खुद इसके बारे में संशकित थे। उन्होंने इसे अपनी एक 'भूल' भी माना था।

दरअसल डार्क एनर्जी ऐसी अनजानी ऊर्जा को माना गया है कि जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और आकाशीय पिंड एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड का सत्तर फीसद हिस्सा इसी ऊर्जा से बना है। हालांकि यह ऊर्जा क्या है किसी को नहीं पता। कई वैज्ञानिक हजारों-लाखों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करके इस अनजानी ऊर्जा और इसके गुणों को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जो तथ्य और आंकड़े मिले हैं, उनसे साबित होता है कि जिसे आइंस्टीन 'भूल' मानते थे, वह भी उनकी प्रतिभा का एक कमाल था जो आज सच साबित हो रहा है।

दरअसल अभी तक खगोलविद और भौतिक विज्ञानी डार्क मैटर की व्याख्या नहीं कर सके हैं। यह रहस्यमय पदार्थ ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं से लेकर कॉस्मिक तरंगों तक हर महान संरचना के द्रव्यमान का अस्सी फीसद से अधिक बनाता है। एक रोमांचक संभावना यह है कि ब्लैक होल से डार्क मैटर की उत्पत्ति होती है। डार्क मैटर की तरह ब्लैक होल से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। ब्लैक होल डार्क मैटर के लिए एक प्राकृतिक व्याख्या है। लेकिन खगोलविद लंबे समय से जानते हैं कि तारकीय द्रव्यमान वाले सामान्य ब्लैक होल ब्रह्मांड के काले पदार्थ की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास में ज्ञात डार्क मैटर के लिए पर्याप्त ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त तारे नहीं बने हैं। ब्रह्मांड में ब्लैक होल एक ऐसा रहस्यमय पिंड माना जाता है जो गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाता है, लेकिन प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता। यह छोटे-छोटे कणों से बना हो सकता है। पर अब एक नए सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल क्वांटम पैकेटों से बने हो सकते हैं जो उप-परमाणु कणों के साथ होते हैं और जिन्हें फर्मियन के रूप में जाना जाता है। ये ब्रह्मांड के बचपन के दौरान तंग पैकेटों में एक साथ लिप्त हो गए माने जाते हैं। ब्रह्मांड में शुरुआती क्षणों ने एक सुंदर आश्चर्यजनक काया की पेशकश की। हो सकता है कि उस समय यही चल रहा था, जिससे अरबों-खरबों छोटे ब्लैक होल बनते रहे होंगे। ये ब्लैक होल आज तक बने रह सकते हैं और संभवतः डार्क मैटर की पहेली को सुलझा सकते हैं। अब पता चला है कि अंतरिक्ष का पनचानवे फीसद हिस्सा अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा से मिल कर बना है। बाकी पांच फीसद हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि यह अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा ही वह कड़ी है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिल कर बने हैं जो प्रकाश को सोख, छोड़ और परावर्तित नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि यह अदृश्य पदार्थ और ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता। अब तक के शोधों से यह पता चला है कि गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाशगंगा का अंतरजोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है। वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते। पर आज ये सभी स्थिर हैं। ऐसा क्यों है ऐसा तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान से पांच गुना अधिक द्रव्यमान हो। यहीं से अदृश्य पदार्थ यानी डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई। यह डार्क मैटर ही है जो ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर डोककुम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई 44 नामक आकाशगंगा का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हों कम तारों के साथ भी यह आकाशगंगा स्थिर थी। ये काफी चैकाने वाला विषय था, क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते। ऐसे में वे पथ से भटक जाएंगे। डोककुम और उनकी टीम ने यह अनुमान लगाया हो न हो, पर कुछ ऐसा जरूर है जो इस आकाशगंगा को स्थिर रख रहा है। उनके प्रयोगों की जांच के जो नतीजे सामने आए, वे चौंकाने वाले थे।